



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 333]
No. 333]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 1983/श्रावण 11, 1905
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 1983/ SRAVANA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 2 अगस्त 1983

का०आ० 547(अ)/18 कक/आई डी आर ए/83:—
भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० 65(अ)/18-कक/आई डी आर ए/78 तारीख 4 फरवरी, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) आन्ध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले के बोविली में चीनी विनिर्माण करने वाले मैसर्स श्रीराम शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के एकक का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 901 (अ), तारीख 21 नवम्बर 1980; का० आ० 619 (अ), तारीख 3 अगस्त 1981; का० आ० 549 (अ), तारीख 2 अगस्त 1982 और का० आ० 83(अ)/81 कक आई डी आर ए/83, तारीख 2 फरवरी, 1983 द्वारा उक्त आदेश 2 अगस्त, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए जारी रखा गया था।

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम 2 फरवरी 1984 तक की (जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है), छह मास की और अवधि के लिए निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन बना रहे;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 2 फरवरी, 1984

तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 4/4/78-सीयूएस]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDERS

New Delhi, the 2nd August, 1983

S.O. 547(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 65(E)|18AA|IDRA|78, dated the 4th February, 1978 (hereinafter referred to as the said order), the management of the Unit of Messrs Sri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Bobbili in District Srikulam in the State of Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years from the date of publication of the said Order in the Official Gazette and the Nizam Sugar Factory Limited was authorised to take over management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 90(E), dated the 21st November, 1980; S.O. 619(E), dated the 3rd August, 1981; S.O. 549(E) dated the 2nd August, 1982 and S.O. 83(E)|18AA|IDRA|83 dated 2nd February, 1983 respectively the said Order was continued for a period upto and inclusive of 2nd August, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Nizam Sugar Factory Limited for a further period of six months upto and inclusive of the 2nd February, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 2nd February, 1984.

[F. No. 4/4/78-CUS]

का०आ० 548 (अ) 18वख/आई डी आर ए/83.—
केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ०

958(अ)/18वख/आई डी आर ए/80, तारीख 10 दिसम्बर 1980 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 वख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों परिनिर्धारणों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो 4 फरवरी, 1978 के पश्चात् किए गए हैं या प्रवृत्त हुए हैं) जिनका आन्ध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले के बोंबिली में चीनी का विनिर्माण करने वाले मसर्स श्री राम शुगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का एकक या उक्त एकक का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त एकक या कम्पनी को लागू हों, प्रवर्तन 3 अगस्त, 1981 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पहले उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे।

और, केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 622(अ)/18-वख/आईडीआर ए/81, तारीख 4 अगस्त, 1981; का०आ० 550(अ)/18 वख/आई डी आर ए/82, तारीख 2 अगस्त, 1982 और का० आ० 82(अ)/18वख/आई डी आर ए/83 तारीख 2 फरवरी, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं, 2 अगस्त, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, जारी रखा गया था,

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) 2 फरवरी, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 वख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि को सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) 2 फरवरी, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा सं० 4/4/78-सीयूएस]
ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

S.O. 548(E)|18FB|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 958(E)|18FB|IDRA|80, dated the 10th December, 1980 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those which have been entered into, arrived at or come into force after the 4th February, 1978), to which the unit of Messrs Sri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Bobbili in District Srikakulam in the State of Andhra Pradesh or the company owning the said unit is a party or which may be applicable to the said unit or company, shall remain suspended for a period upto and inclusive of the 3rd August, 1981 and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising there under before the date of issue of the said order shall remain suspended for the said period;

And, whereas, by the Order of Central Government in the Ministry of Industry (Department of

Industrial Development) No. S.O. 622(E)|18FB|IDRA|81, dated the 4th August, 1981, S.O. 550(E)|18FB|IDRA|82, dated the 22nd August, 1982 and S.O. 82(E)|18FB|IDRA|83, dated the 2nd February, 1983 respectively the duration of the said Order was continued upto and inclusive of 2nd August, 1983 (in respect of all matters except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions):

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order in respect of all matters (except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) should be extended for a further period of six months upto and inclusive of 2nd February, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby extends the duration of the said Order in respect of all matters (except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) for a further period of six months upto and inclusive of 2nd February, 1984.

[F. No. 4/478-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

